

सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023

प्रलिस के लयः

[बौधक संपदा अधकार](#), [केंद्रीय फलम परमाणन बोरड](#), सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952, श्याम बेनेगल समतऱ, IT नयऱ 2021

मेन्स के लयः

सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन

चरचा में क्यौं?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023 पारतऱ कयऱ। यह वधियक सेंसरशपऱ से लेकर [कॉपीराइट](#) तक को कवर करने के लयऱ कानून के दायरे का वसुतार करता है और सखत एंटी-पाइरेसी प्रावधान पेश करता है।

- इस वधियक का उद्देश्य मौजूदा सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 में संशोधन करना है।

सनिमैटोग्राफ (संशोधन) वधियक, 2023 में प्रस्तावतऱ प्रावधानः

- पायरेसी वरऱधी प्रावधानः** इस वधियक का उद्देश्य अनधकृत ऑडयो-वजुअल रकॉर्डगऱ और कॉपीराइट सामग्री के वतऱरण में शामिल वयक्तयऱों पर सखत दंड लगाकर फलमों की पायरेसी को रोकना है। इन प्रावधानों में शामिल हैं:
 - सज़ा: 3 महीने से 3 वर्ष तक की कैद।
 - जुरमाना: 3 लाख रुपए से ऑडिटड सकल उत्पादन लागत का 5% तक।
- कॉपीराइट कवरेज का वसुतारः** इसका उद्देश्य सनिमैटोग्राफ अधनियम, 1952 जो कऱ मुख्य रूप से सेंसरशपऱ पर केंदरतऱ था, के कवरेज का वसुतार करते हुए कॉपीराइट सुरक्षा को भी इसके दायरे में लाना है।
 - यह कदम फलम वतऱरण के उभरते परदृश्य के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य फलम नरऱमाताओं और सामग्री नरऱमाताओं के बौधक संपदा अधकारों की रक्षा करना है।
- CBFC पर सरकार की सीमतऱ शक्तयऱऱेंः** यह [केंद्रीय फलम परमाणन बोरड \(CBFC\)](#) की स्वायत्तता पर ज़ोर देता है।
 - के.एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ (2000) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नरऱणय के आधार पर सरकार CBFC द्वारा लयऱ गए नरऱणयों में संशोधन नहीं कर सकती है।
- आयु आधारतऱ रेटगऱ (U/A रेटगऱ):** संशोधन वधियक उन फलमों के लयऱ एक नई आयु आधारतऱ रेटगऱ प्रणाली प्रस्तुत करता है जनके लयऱ अभभावकों या माता-पता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वर्तमान U/A रेटगऱ, जो व्यापक आयु सीमा को कवर करतऱ है, को तीन भन्ऱन-भन्ऱन श्रेणयऱों में वभाजतऱ कयऱ जाएगा:
 - U/A 7+:** माता-पता या अभभावक के मार्गदर्शन में 7 वर्ष से अधकऱ उमर के बच्चों के लयऱ उपयुक्त फलमों।
 - U/A 13+:** माता-पता या अभभावक के मार्गदर्शन में 13 वर्ष से अधकऱ उमर के बच्चों के लयऱ उपयुक्त फलमों।
 - U/A 16+:** माता-पता या अभभावक के मार्गदर्शन में 16 वर्ष से अधकऱ उमर के बच्चों के लयऱ उपयुक्त फलमों।
 - यह नवीन वर्गीकरण प्रणाली [सूचना प्रौद्योगकऱ नयऱ, 2021](#) और [श्याम बेनेगल समतऱ](#) की सफारशऱ (2017) के आधार पर स्टरीमगऱ प्लेटफॉर्म के लयऱ लागू श्रेणीबद्ध-आयु वर्गीकरण के साथ संरेखतऱ है।
- TV एवं अन्य मीडयऱा के लयऱ पुनः प्रमाणनः** वर्ष 2004 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् से वयस्क/एडल्ट रेटगऱ वाली फलमों को टेलीवज़न पर प्रतऱबंधतऱ कर दयऱा गया है।
 - जसके परणामस्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फलमों में कटौतऱ करते हैं और U/A रेटगऱ के लयऱ CBFC से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं।
 - यह वधियक इस प्रथा को औपचारकऱ बनाता है, जसके तहत फलमों को टेलीवज़न और "अन्य मीडयऱा" के माध्यम से प्रसारण के लयऱ पुनः प्रमाणतऱ कयऱ जा सकेगा।
- प्रमाणपत्रों की सथायी वैधताः** इस अधनियम में संशोधन के माध्यम CBFC प्रमाणपत्रों की 10 वर्ष की वैधता संबंधी प्रतऱबंध को हटाकर उन्हें सथायी वैधता प्रदान की जा सकेगी।

सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:

- **सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** को संसद द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमि किये गया था कि फलिमों का प्रदर्शन भारतीय समाज की सहनशीलता की सीमा के अनुसार हो।
 - यह फलिमों को प्रमाणित करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत नरिधारित करता है, इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता अथवा नैतिकता या मानहानि या न्यायालय की अवमानना जैसे विषय शामिल हैं।
- इस अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड (जसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है) की स्थापना का प्रावधान करती है।
 - CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फलिमों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नरियंत्रित करता है।
- यह बोर्ड के नरिणयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cinematograph-amendment-bill,-2023>

